यहां पर जो प्राइवेट दूध की डेरियां बनी हुई थीं उन को वहां से हटा दिया गया है। इस के अलावा जो दिल्ली मिल्क स्कीम का काम किया गया है वह एक हाथी के समान है जिसके कि दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैंवह दिल्ली की आम जनता को उस की मिनिमम नीड्स का भी दूध नहीं दे पाते हैं और इस का मुख्य कारण यह है कि दिल्ली के अन्दर दूध का समुचित प्रबन्ध नहीं और दिल्ली मिल्क स्पलाई स्कीम की 7 मशीनें लगी हुई हैं।..क्या यह सत्य है कि दिल्ली के इर्द-गिर्द जहां-जहां से दूध मिलता है वहां कारखाने लग गये हैं मिल्क पाउडर बनाने के और इसलिए वहा से दिल्ली में जो दूध आ सकता है वह दूध नहीं आता और इसलिए अस्पतालों को वह नहीं मिल सकता इसलिए गवर्नमेंट क्या इस के लिए कोई पग उठाने जा रही है जिससे कि दिल्ली के इर्द-गिर्द के इलाक़ों का जो दूध है वह उन फैक्टरियों में जाने के बजाय दिल्ली में आ सके ?

MR. SPEAKER : You are going into an entirely different question.

SHRI BAL RAJ MADHOK : No, Sir, it is a relevant question connected with milk powder.

MR. SPEAKER : I will have to decide whether it is relevant or not. Let us go to the next question.

UNAUTHORISED HUTS IN THE CAPITAL

+

*665, SHRI BAL RAJ MADHOK :
SHRI MARANDI :
SHRI MAYAVAN :

Will the Minister of WORKS HOUSING AND SUPPLY be pleased ot state :

(a) whether it is a fact that a high level Committee has been set up by his Ministry to go into the question of unauthorised huts in the capital;

(b) if so, whether any report has been submitted; and

(c) how many of the recommendations of this Committee have been accepted and implemented ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) In a meeting held under the chairmanship of the Home Minister, a Study Group with the Minister of Works, Housing and Supply as Chairman was set up to consider the jhuggi and jhopri problem in Delhi.

(b) Yes.

(c) The recommendations of the Study Group are under consideration of the Government.

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि इस स्टडी ग्रुप ने यह सुझाव दिया है कि दिल्ली के अन्दर जितनी अनऐथोराइज्ड झुग्गियां हैं उन को शीघ्रातिशीघ्र हटा दिया जाय ताकि वह जो नई जगह पर उन को ले जाकर बसाना है वहां वह बस सकें और आज जो उन के मन में दुविधा है कि वह हटा दिये जायेंगे उस के बारे में सरकार का क्या मत है ?

श्री इकबाल सिंह : यह स्टडी ग्रुप दिल्ली की झुग्गी और झोंपड़ी समस्या पर विचार करने के लिए बना था। दिल्ली में जो अनऐथोराइज्ड आदमी गवर्नमेंट लैंड पर बैठे है उनको जल्द से जल्द उस इलाके से हटाया जाय और अगर हटाया जाय तो उन को क्या क्या सुविधाएं दी जायें, जो आदमी एलिजिबल हैं और जो अनएलिजिबल हैं उन के बारे में एक फेज्ड प्रोग्राम बनाया जाय और उस प्रोग्राम के मुताबिक चला जाय ताकि किसी आदमी को उस बारे में ऐतराज न हो कि यह क्यों हुआ ? किसी के साथ ज्यादती न हो इस तरह से इस सारी समस्या का समाधान निकाल कर जल्द से जल्द उस का सामना करना चाहिए यह स्टडी ग्रुप ने तय किया है।

श्री बलराज मधोक : यह जो एलिजिबल लोगों को हम 25 गज का प्लाट दे रहे हैं तो उस के बारे में कोई डवलपमट करने का और वहां उन को कोई पक्का स्ट्रक्चर बनाने का भी अधिकार दिया जायगा ?

श्री इकबाल सिंह : जो स्टडी ग्रुप ने सिफारिशें की हैं उन में से एक यह भी सोचा गया है कि यह 25 गज के प्लाट्स जिन आदमियों को दिये जायें उन को तीन, चार सालों में अगर उन की क़ीमत किसी ढंग से किश्तों में वह अदा कर सकें तो उन को वह दे दिये जायें। यह एक सिफारिश है।

श्री क० ना० तिवारी : सन् 1967 में कितने झुग्गी झोंपड़ी वालों को उन की पुरानी जगहों से हटाया गया और उन में से कितनों को प्रशासन द्वारा बसाया गया ? क्या इस तरह के लोग भी हटाये गये हैं जोकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करते हैं और उन को हटाये जाने से उन की वह स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज बन्द हो गयीं और उन को प्रशासन द्वारा अन्यत्र जगह नहीं दी गई ?

श्री इकबाल सिंह : इस समय तो मेरे पास यह दिल्ली के तमाम आंकड़े नहीं हैं कि पिछले साल कितने लोग हटाये गये लेकिन बहुत सी जगहों के लोगों को हम ने हटाया और उन हटाये हुए आदमियों में जो एलिजिबल आदमी थे उन को हम ने दूसरी जगह आलटरनेटिव जगह दी है बाक़ी ऐसे अनएलिजिबल आदमी जोकि उन झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे थे उन को भी जहां तक सम्भव हो सका है दूसरी जगह ले जाकर बैठाया गया है लेकिन सब के लिए यह बात नहीं कही जा सकती है। जहां तक कमर्शियल की बात है या कोई ख़ास काम का ताल्लुक है तो ऐसे लोग जो गवर्नमेंट की ज़मीन पर बगैर किसी हक के अनलाफुली बैठ गये थे उन को अलबत्ता जब वहां से हटाया गया तो सरकार द्वारा उन्हें कोई उस के लिए दूसरी जगह देने का बंदोबस्त नहीं है और उन्हें खुद उस के लिये कोशिश करनी है।

श्री जार्ज फरनेंडीज : इस देश में बेघर लोगों को बसाने के लिए लगभग साढ़े सात करोड़ मकानों की आवश्यकता है तो मैं जानना चाहता हू कि क्या सरकार कोई ऐसी भी नीति अपनायेगी कि जिससे उन तमाम झुग्गियों में रहने वाले लोगों को चाहे वह एलिजिबल हों अथवा इनएलिजिबल हों, उस में कोई फर्क न करते हुए, उन सब के वास्ते कोई न कोई तरीक़े से मकानों का इंतज़ाम किया जाय ?

श्री इकबाल सिंह : यह बात ठीक है कि हमारे देश में कोई साढ़े सात करोड़ मकानों की आवश्यकता है, यह ऐसे मकान हैं जो दुबारा बनने चाहिएं या जिनमें कोई सुधार होना चाहिए और जो नये बनने चाहिएं लेकिन उस के लिए 30 हज़ार करोड़ से ज्यादा रुपया चाहिए और आज हमारे पास उतने साधन सुलभ नहीं हैं तो सरकार के पास जितने साधन सुलभ हैं जितना रुपया पास है उस में ही इस बारे में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करना चाहिए और वह ही हमारे द्वारा किया जा रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमन्, आजकल सर्दी के दिन हैं, दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है तो क्या यह झुग्गी-झोंपड़ी वालों को हटानें का काम सर्दी समाप्त होनें तक के लिए नहीं रोका जा सकता था ?

श्री इकबाल सिंह : जहां तक दिल्ली में इन झुग्गी-झोंपड़ी वालों को वहां से उठाने का सवाल है तो उस के लिए प्रशासन द्वारा पहले से प्रोग्राम बन जाता है और वह प्रोग्राम एक कमेटी के सामने आया था कि उन के लिए आलटरनेटिव जिस जगह पर जाना हो उस के लिए प्रबन्ध कर दिया जाता है और उस के बाद ही उन को उठाया जाता है। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि अब सर्दी है, अब बरसात है तो यह उठानें का प्रोग्राम चल नहीं सकता है लेकिन यह जरूर है कि अगर बरसात हो तो उन दिनों में उन को नहीं उठाया जाता है।

श्री प्रेम चंद वर्मा : मैं पूछना चाहता हूं कि वह 1966 में जितने झुग्गी-झोंपड़ी वाले लोग थे वह 1967 में किस तरीक़े से उस के

डेढ़ गुने हो गये और क्या इस झुग्गी-झोंपड़ी के मामलें में अधिक लोगों के बढ़ने का कारण यह सरकारी कर्मचारी लोग हैं जोकि वहां उन जगहों पर बैठ जाते हैं और उस का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और क्या यह भी दुरुस्त है कि जिन लोगों की कोठियां बनी हुई हैं उन लोगों ने इस झुग्गी-झोंपड़ी स्कीम में अपने लिए ज़मीन ऐलाटमेंट कराई है ?

श्री इकबाल सिंह : मेरे पास कोई इस तरीक़े की इनफ़ारमेशन नहीं है बाक़ी अगर माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई इत्तिला हो तो वह मुझे लिख कर भेजें और मैं उस की इनक्वायरी कराऊंगा ।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अखबारों में उस की चर्चा हो रही है और मंत्री जी कहते हैं कि उन्हें उस का पता नहीं है. . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री कंवर लाल गुप्त : सन् 1961 में दिल्ली में करीब 25,000 झोंपड़ियां थीं और अभी आप का यह क्लिएरेंस का काम चल रहा है लेकिन आज दिल्ली में करीब 1 लाख 10 हज़ार झोंपड़ियां हैं, उन में से काफ़ी आप नें हटा भी दी हैं लेकिन उस के बाद भी अभी यह झोंपड़ियां काफ़ी स्पीड से बढ़ रही हैं यानी १ साल में 25,000 के करीब नई झोंपड़ियां बनती हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि नई झोंपड़ियां न बनें और आप ने उसे एक ओफैंस भी बनाया है कि ऐसा करने वाला व्यक्ति पकड़ा जायगा लेकिन उस के बाद भी झोंपड़ियां बनती चली जा रही हैं तो आप कि इस स्टडी ग्रुप नें क्या सिफारिशें की हैं ? ताकि नई झोंपड़ियां न बनें । मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा यह है कि 31-3-68 तक अभी चार महीने बाक़ी हैं और इस दौरान में आप इन झुग्गी झोंपड़ी वालों को कोई आल्टर-नेटिव जगह देने वाले हैं और देने वाले हैं तो कितनों को देने वाले हैं ?

श्री इकबाल सिंह : जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि नई झोंपड़ियां न बनें यह तो दल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वह देखे कि नई झोंपड़ियां न बनें या जो इनका प्रबन्ध करते हैं उनको यह देखना है कि न बनें । यह उन के जिम्मे काम है कि वे इनको न बननें दें । जो बनी हुई हैं उनको हटानें का जहां तक ताल्लुक है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन फेज्ड स्कीम बनाती है और उसके मुताबिक काम चलता है । जहां तक स्टडी ग्रुप का सम्बन्ध है उसने सुझाव दिया है कि एक आर्डिनेंस बनाया जाए ताकि अगर कोई आदमी गवर्नमेंट की ज़मीन पर कब्ज़ा करता है उसको सज़ा दी जा सके और उस पर जुर्माना किया जा सके । ला मिनिस्ट्री के साथ इसके बारे में सलाह मश्विरा किया जा रहा है और उसके बाद कोई फैसला किया जाए ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने यह भी पूछा था कि 31-3-68 तक हटाने का कोई प्रोग्राम लोकल बाडीज़ नें तय करके आपको दिया है ?

श्री इकबाल सिंह : यह तो दिल्ली एड-मिनिस्ट्रेशन और म्यूनिसिपल कारपोरेशन करती है । जितने प्लाट तैयार होंगे उसके मुताबिक ही लोगों को हटाया जाएगा । जिस हिसाब से प्लाट तैयर होते हैं उस हिसाब से इनको हटाया जाता है । हर चीज़ का फैसला दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को और दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन को करना होता है । टारगेट भी उनको बनाने होते हैं । कितनी फैसिलिटीज़ देनी है, हमें तो यही देखना होता है ।

श्री शिव नारायण : यह बताया गया कि एक लाख दस हज़ार झुग्गियां यहां हैं और अगर एक-एक झुग्गी में पांच पांच आदमी भी हम लगायें तो इनकी तादाद पांच लाख से ऊपर जाती है । मैं जानना चाहता हूं

कि पांच लाख में से कितने हरिजन हैं और उनके लिए आपने क्या प्रबन्ध किया है। हरिजन कालोनी जो गांधी जी ने बनाई थी दिल्ली में वहां इनको बसाने का आप क्या इंतजाम कर रहे हैं ?

श्री इकबाल सिंह : अंदाज़ा यह है कि कि एक लाख और एक लाख दस हज़ार के करीब झुग्गियां दिल्ली में हैं। अगर उन में रहने वाले लोगों की तादाद को देखा जाए तो यह सही है कि उनकी आबादी कोई चार पांच लाख के करीब हो सकती है। इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया गया है कि इन में कितने हरिजन हैं और कितने दूसरे हैं।

श्री राम चरण : दिल्ली में तीन प्रकार के आदमी रहते हैं। एक तो वे आदमी हैं जो अपने मकान बना कर चार चार और छः छः उनको किराये पर उठा देते हैं। दूसरे वे हैं जो किराये के मकानों में रहते हैं। तीसरे वे हैं जिन के पास किराये का पैसा देने के लिए नहीं होता है और जो इस तरह से झुग्गियां बना कर रहते हैं और इन में हरिजन तथा दूसरे गरीब मजदूर आते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि एक या डेढ़ रुपया रोज़ाना कमा कर अपना गुज़ारा करते हैं और झुग्गियां डाल कर जिन्दगी बसर करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिन के पास तीन-तीन और चार चार मकान हैं उनके मकानों को एक को छोड़ कर जो कि उनके रहने के लिए जरूरी है बाकियों को डिमालिश करके छोटे-छोटे मकान उन जगहों पर बना कर इन झुग्गी वालों को आप देंगे और इस तरह से आप उनको बसायेंगे ? क्या सरकार इसके लिये तैयार है ?

श्री इकबाल सिंह : यहां पर सवाल तो इतना ही है कि जो आदमी गवर्नमेंट की ज़मीन पर बैठता है और उसको बैठने का हक नहीं है, उसको हमने हटाना है।

श्री राम चरण : रहने का हक सब को है या नहीं है ?

श्री इकबाल सिंह : जहां तक गरीब आदमियों का ताल्लुक है, सारे देश में और भी गरीब आदमी हैं और दिल्ली में भी गरीब आदमी हैं। दिल्ली के गरीब आदमियों के लिए हम क्या कर रहे हैं यह तो आपको मालूम ही है। जितना उनके लिए किया जा सकता है हम कर रहे हैं। आपको यह भी सोचना होगा कि देश में और जो गरीब आदमी हैं, उनके लिए भी कुछ किया जाए।

श्री मोलहू प्रसाद : मकानों की समस्या जटिल होती जा रही है। यह दिल्ली की ही बात नहीं है, बम्बई, कलकत्ता आदि सभी बड़े-बड़े शहरों में जटिल होती जा रही है। क्या इसका कारण यह नहीं है कि सारे जितने कारखाने हैं या कार्यालय हैं वे शहरों में ही केन्द्रित होते जा रहे हैं और इस कारण से देहातों के लोग शहरों की तरफ आते जा रहे हैं ? यदि हां तो इसको देखते हुए और मकानों की भी समस्या को हल करने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है जिससे कारखानों और कार्यालयों को विकेन्द्रित किया जा सके ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस पर विचार किया है और अगर किया है तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

MR. SPEAKER : It is about Delhi. He can answer about Delhi if he has some information.

श्री इकबाल सिंह : अगर कहीं पर कारखानें बनते हैं तो उस के मुताबिक वे मजदूरों के लिए मकान भी बनाते हैं। सरकार के पास यह प्रोग्राम है कि कारखानों का सारे देश में डिसपर्सल किया जाए।

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER : No, not so many of you. He was asking about Bombay, Calcutta and all places. I think, I will have to go to the next question. It is not a discussion. I cannot allow so many of them now. At least, 20 or 30 of you more want to put a supplementary; I cannot allow this. It has been answered sufficiently enough.

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : May I know what percentage of the needs of those people who are entitled to allotment of plots on account of the removal of the unauthorised huts has been met ?

श्री इकबाल सिंह : आज तक तकरीबन पचास हजार आदमी थे जो कि एलिजिबल थे और जिन को प्लाट दिये जानें थे । इन में से 21,000 के करीब आदमियों को प्लाट दिए गए हैं और इन में कोई सात आठ हजार के करीब ऐसे हैं जो प्लाटेस पाने के लिए एलिजिबल नहीं थे । उन से ज्यादा किराया लिया जाता है । चौंतीस हजार के करीब ऐसे आदमी हैं जिन को प्लाट देने ह ।

श्री ओ० प्र० त्यागी : झोंपड़ियों में रहने वाले अधिकांश आदमी गरीब हैं और जो इनको आल्टरनेटिव जगह दी गई है वह ऐसी जगह पर दी गई है जो शहर से दूर है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे वहां रह सकेंगे ? क्या वे लौटकर कर नहीं आ जाते हैं ? क्या सरकार उनको जमीन के साथ-साथ काम देनें की भी कोई व्यवस्था करेगी ताकि वे जिन स्थानों पर उनको भेजा गया है, वहां बने रह सकें ?

श्री इकबाल सिंह : जहां तक कालोनीज का सम्बन्ध है जहां जमीन मिल सकती है वहां ही कालोनीज बनाते हैं । हमारी कोशिश यही होती है कि नजदीक उनकी कालोनीज बनाई जाएं । लेकिन मुश्किल यह है कि नजदीक एक तो जमीन है नहीं और अगर है तो उसके दाम बहुत अधिक हैं । अगर अधिक दाम दिये जयें तो बहुत कम प्लाट बन सकेंगे । इस वास्ते सब चीज को देखना होगा । कालोनीज बनाते समय सब चीज का ध्यान रखा जाता है । नजदीक जमीन न होने के कारण नजदीक दी नहीं जा सकती है ।

SHRI S. M. BANERJEE : I would like to know whether the hon. Minister is aware that because an international conference is going to be held in the Oberoi Hotel Continental, to make that place neat and clean, all those people who were staying in those jhuggies just near the Oberoi Hotel are being removed forcibly; if so, I would like to know whether they have been given alternative accommodation before removal.

श्री इकबाल सिंह : कहां से झुग्गियां हटानी हैं इसका फैसला दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन को करना होता है ।

श्री चंद्रिका प्रसाद : झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों का प्रदेश वाइज आंकड़ा क्या है । विशेष कर मैं जानना चाहता हूं कि ईस्ट यू० पी० और वैस्ट बिहार के कितने लोग इन में हैं ?

MR. SPEAKER : I do not think we have satistics about it.

श्री शिव चरण लाल : झुग्गियों में रहने वाले लोगों को आप दिल्ली के बाहर बसा रहे हैं । इन में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो लोग नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं उनको आने जाने की सुविधा हो, इसके लिए आप क्या प्रबन्ध कर रहे हैं ? क्या आप उनको कोई सुविधा प्रदान करेंगे ताकि वे नौकरी पर आ जा सकें ?

श्री इकबाल सिंह : यह सरकारी कर्मचारियों का सवाल नहीं है । यह बिल्कुल अलग सवाल है ।

FERTILIZER FACTORIES IN PUNJAB

*669. SHRI YAJNA DATT SHARMA: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether Punjab Government have approached the Centre for technical help in setting up fertilizer factories to boost up wheat output in the State; and

(b) if so, the details of the help sought for and the Centre's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) and (b). Yes, Sir. The proposal is to set up